

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 929 राँची, मंगलवार,

राँची, मंगलवार, 19 नवम्बर, 2019 (ई॰)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

13 नवम्बर, 2019

संख्या- 5/आरोप-1-444/2014 का॰-9040-- श्री नरेश कुमार, सेवानिवृत्त झा॰प्र॰से॰ (कोटि क्रमांक-266/03, गृह जिला-मुंगेर), तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल, राँची के विरूद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-09/रा॰, दिनांक 08.01.2004, पत्रांक-36/रा॰, दिनांक 10.01.2004 एवं अपर समाहत्त्र्ता, राँची के पत्रांक-29(i), दिनांक 27.01.2004 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध मौजा हुंडरू के खाता सं0-360, प्लॉट सं॰-1260, कुल रक्तबा 10.50 एकड़ भूमि, जो आर0एस0 खितयान में गैर मजरूआ मालिक के रूप में दर्ज है, को जय भवानी सहकारिता गृह निर्माण सिमिति, हिनू के नाम से स्वीकृत करने एवं बाद में जय भवानी सहकारिता गृह निर्माण सिमिति, हिनू द्वारा कुल 75 व्यक्तियों के नाम से बिक्री की गई भूमि को दाखिल खारिज स्वीकृत करने, सरकार को गंभीर आर्थिक क्षति पहुँचाने एवं एक बड़े कीमती भूखण्ड से वंचित करने का प्रयास करने तथा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

उक्त के लिए विभागीय पत्रांक-2518, दिनांक 14.05.2004 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-837, 838 एवं 839, दिनांक 10.08.2004 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प संख्या-4742, दिनांक 31.12.2005 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री के॰ विद्यासागर, तत्कालीन सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर अनुवर्ती संकल्पों द्वारा जाँच पदाधिकारी बदलते हुए विभागीय संकल्प सं0-7840, दिनांक-09.09.2016 द्वारा श्री विनोद चन्द्र झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी, श्री झा के पत्रांक-294, दिनांक-06.10.2017 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् इनके पेंशन से 20% राशि की कटौती 10 वर्षों तक करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-324, दिनांक 11.01.2019 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। इसके अनुपालन इनके द्वारा पत्र, दिनांक-15.02.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है बल्कि वही तथ्य दोहराये गये, जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने बचाव बयान में रखे थे।

समीक्षोपरांत, श्री कुमार के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् इनके पेंशन से 20% राशि की कटौती 10 वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किये जाने के निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसके उपरांत विभागीय पत्रांक-4915, दिनांक 21.06.2019 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध उक्त दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमित की माँग की गयी। उक्त के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-2220, दिनांक 25.09.2019 द्वारा सहमित प्रदान की गयी है।

अतः श्री नरेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल, राँची के विरूद्ध पेंशन से 20% राशि की कटौती 10 वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान, सरकार के संयुक्त सचिव।
